आज के भारत की ज्वलंत समस्याएं-19

राष्ट्र की जरूरत राम मंदिर
या
सामाजिक अन्यायमुक्त भारत निर्माण !

एच.एल. दुसाध

आज के भारत की ज्वलंत समस्याएं-19

राष्ट्र की जरूरत

राम मंदिर या सामाजिक अन्यायमुक्त भारत निर्माण

एच. एल. दुसाध

दुसाध प्रकाशन
लखनऊ

प्रथम संस्करण : 2018
द्वितीय संस्करण : 2020

ISBN : 978-81-87618-77-5

बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के लिए
द्वारा
प्रकाशक : **दुसाध प्रकाशन**
डाइवर्सिटी हाउस, 2/1467,
आदिल नगर, कल्याणपुर, लखनऊ-226022
E-mail : hl.dusadh@gmail.com
मो. : 9654816191

प्रशासनिक कार्यालय
बी-1, 149/9 किशन गढ़, वसंत कुंज,
नई दिल्ली-110070
संपर्क : 011-26125979, 9654816191

© **लेखक**

मूल्य : पेपर बैक : 150 रुपए
सजिल्द : 300 रुपए

रचना	:	**राष्ट्र की जरूरत** **राम मंदिर या सामाजिक अन्यायमुक्त भारत निर्माण**
लेखक	:	एच.एल. दुसाध
आवरण	:	डॉ. लाल रत्नाकर
शब्दांकन एवं मुद्रण	:	क्विक ऑफसेट, दिल्ली-94

समर्पित

बहुजन समाज की मुक्ति में
सदा निमग्न, असाधारण चित्रकार
डॉ. लाल रत्नाकर को

अनुक्रम

अपनी बात 7

ताज पर विवाद—9, 'नव्य अयोध्या'—10, अयोध्या में ऐतिहासिक दीपोत्सव—10, भाजपा को शिकस्त देना पहले से कठिन!—12, नीतीश की पलटी—12, मृतप्राय बहुजन नेतृत्व—13, योग्य नेतृत्व का अभाव—13, सावधान! मोदी को सामाजिक न्याय का नया मसीहा बनाने कि तैयारी चल रही है—14, भाजपा की शक्ति के स्रोत—14, बहुजनवादी दलों की शक्ति का स्रोत : सामाजिक अन्याय का शिकार विशालतम आबादी—15, बहुजनों की सापेक्षिक वंचना : भाजपा के खिलाफ साबित हो सकती है बारूद का ढेर!—16, एक ही कमी : योग्य बहुजन नेतृत्व!—17, सापेक्षिक वंचना के सद्व्यवहार के लिए : डाइवर्सिटी—18, सामाजिक अन्यायमुक्त भारत निर्माण बने चुनावी मुद्दा—19, मोदी को सामाजिक न्याय का मसीहा बनाने के मंसूबों पर : डाइवर्सिटी फेर सकती है पानी—19, डाइवर्सिटी बहुजन नेताओं को भारत का ताज पहना सकती है—20

अध्याय-1

यूपी चुनाव में गायब : सामाजिक न्याय का मुद्दा

काले धन के विमर्श के भंवर से निकलने की जरुरत 25
मोदी-मुक्त भारत का सपना 28
यूपी वाले कैसे बचायेंगे देश! 31
विकास और बहुजन की असल तस्वीर 35
भाजपा कैसे बन गयी अप्रतिरोध्य! 38
यूपी चुनाव परिणाम की घोषणा के पहले से जारी मेरे पोस्ट 42
सहस्राधिक वर्षो के बाद आज होगा : मुकम्मल हिन्दू-राज! 42
आज से बहुजनों की गुलामी के नए दौर की शुरुआत हो सकती है 43
भाजपा की शक्ति से अनजान : यूपी का अदूरदर्शी बहुजन नेतृत्व 44
भाजपा के सर पर प्रत्याशा का अभूतपूर्व बोझ! 44

अध्याय-2
सामाजिक अन्याय पूर्ववत है!

जाति पर धार्मिक चेतना के राजनीतिकरण की जबरदस्त विजय 49
विनिवेश : अब सरकारी उपक्रमों को और तेजी से
निजी क्षेत्र के हाथों में जाना है 52
योगी राज में रामायण सर्किट 56
भाजपा की शक्ति के स्रोत 60
बहुजनवादी दलों की शक्ति का स्रोत 63
सामाजिक अन्याय का शिकार विश्व का विशालतम समाज 63
राम मंदिर का संकल्प लिए : अयोध्या पहुँचे योगी 71
राम मंदिर के लिए : तोगड़िया की हुंकार 75
सावधान! साधु-संत फिर सक्रिय हो रहे हैं 79

अध्याय-3
साक्षात्कार

साक्षात्कार की प्रश्नावली 85
प्रश्नोत्तर 97
डॉ. विजय कुमार त्रिशरण 97
हरिप्रसाद चौधरी 105
सतेन्द्र 113
हरिशंकर शाही 121
संजीव चंदन 124
सोबरन कबीर 125
बुद्धशरण हंस 127
शीलबोधि 139
ज्योतिबा अशोक 142

अपनी बात

डाइवर्सिटी सिद्धांत के प्रति लगाव रखने वाले मेरे नियमित पाठकों को यह पता है कि मैने 2008 में 'तेज विकास की रोशनी से वंचित : बहुजन समाज' से आज के भारत की ज्वलंत समस्याएं शृंखला की किताबें तैयार करने का सिलसिला शुरू किया। इसके पीछे मेरी मंशा यह रही कि मीडिया के अल्पकालिक प्रभाव के कारण जिन महत्वपूर्ण समस्यायों से एक अन्तराल के बाद विमुख होकर लोग, समस्यायों के अंबार में घिरे भारत की दूसरी समस्यायों में खो जाते हैं, उन्हें यदि पुस्तक के रूप में देश प्रबुद्ध विचारकों, साहित्यकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राष्ट्र निर्माताओं के समक्ष परोस जाय तो समस्या पर गंभीरता से बहस होगी और राष्ट्र इनका समाधान ढूंढने के लिए मन बनाएगा। इसीलिए मैंने बंधुवर बृजपाल भारती के उत्साहवर्द्धन से भारत की ज्वलंत समस्या सीरिज की पुस्तकें तैयार करने का मन बनाया। इस कारण ही 2008 से तेज विकास की रोशनी से वंचित : बहुजन समाज से जो सिलसिला शुरू किया उसके बाद एक एक करके सच्चर रिपोर्ट के आईने में मुस्लिम समुदाय की समस्या और समाधान (2008), सेज पर सवाल और नंदी ग्राम में बवाल (2008), आरक्षण पर संघर्ष (2008), आस्था पर अभिव्यक्ति का हमला (2008), भूमंडलीकरण के दौर में ब्राह्मणवाद कितनी बड़ी समस्या (2008), सामाजिक न्याय की राजनीति की हार (2009), मुद्दाविहीन चुनाव में डाइवर्सिटी(2009) स्वतन्त्र मुस्लिम राजनीति की संभावनाएं (2009), महिला सशक्तीकरण में बाधक : शक्ति के केन्द्रों में लैंगिक विविधता की अनदेखी(2010), नक्सलवाद के प्रतिकार का सर्वोत्तम उपाय : डाइवर्सिटी (2010) जाति जनगणना की चुनौतियाँ(2010), हिंदी पट्टी की बदहाली का हल (2010), अरब जनविद्रोह के आईने में : भारत में क्रांति की सम्भावना(2011), जाति उन्मूलन : मार्क्सवादी बनाम आंबेडकरवादी परियोजना (2013), भगाणा की निर्भायायें (2014) कैसे हो संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति (2016), शैक्षणिक परिसरों में पसरा भेदभाव : सवर्ण वर्चस्व का परिणाम (2016) जैसी और 17 किताबें आयीं। आज जिस तरह राम मंदिर निर्माण का मुद्दा बड़ा आकर लेने जा रहा है, उसे देखते हुए आज की समस्याएं शृंखला की यह 19वीं और नवीनतम पुस्तम तैयार करनी पड़ रही है।

वास्तव में 7 अगस्त, 1990 को मंडल रिपोर्ट के जरिये शक्ति के स्रोतों में हजारों साल के वंचितों जो हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई, उसके खिलाफ भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर का जो आन्दोलन छेड़ा उसके फलस्वरूप देश की हजारों करोड़ की सम्पदा और असंख्य लोगों की प्राण-हानि तो हुई ही, इसके साथ प्रभावित हुई देश की एकता और अखंडता। इस आन्दोलन से फायदा हुआ

सिर्फ उस विशेषाधिकारयुक्त व सुविधाभोगी क्षुद्र संख्यक वर्ग का, जिसका सदियों से शक्ति के स्रोतों (आर्थिक-राजनीतिक-धार्मिक-सांस्कृतिक) पर एकाधिकार रहा। इसके फलस्वरूप जहाँ एक ओर राजनीतिक रूप से लाचार समूह में तब्दील हुए विशेषाधिकारी वर्ग के हाथ में सत्ता आई, वहीं दूसरी ओर मंडल के बाद सामाजिक न्याय की आश लगाया विशाल वंचित समुदाय, सामाजिक अन्याय के दलदल में नए सिरे से फंसने के लिए अभिशप्त हुआ। अतः मंदिर मुद्दे की भयावहता का देखते हुए मुझे ज्वलंत समस्याओं की सीरिज में इसे बहुत पहले लाना चाहिए था, यह मानने में मुझे कोई द्विधा नहीं। लेकिन अब भी मैं इस पर पुस्तक लाने का मन नहीं बनाता, यदि मोदी राज में बहुजनों की हुई क्षति मुझे घोरतर रूप से विचलित नहीं की होती।

इस देश के जन्मजात वंचितों के नजरिये से यदि स्वाधीनोत्तर भारत के इतिहास का आंकलन करें तो पाएंगे कि हम मोदी राज में निर्विवाद रूप से सबसे भयावह दौर से से गुजर रहे हैं। इस दौर में आजाद भारत की अन्यतम शक्तिशाली सरकार जो फैसले ले रहे रही है, वह जन्मजात वंचितों के लिए दुःस्वप्न है। इस दौर में श्रम कानूनों को निरंतर कमजोर एवं नियमित मजदूरों की जगह ठेकेदारी प्रथा लागू कर मजदूर वर्ग को अभूतपूर्व शोषण के दलदल में फंसाया जा रहा है।' साफ़ दिख रहा है कि आज भारत की राजनीति पूरी तरह नवउदारवाद के खूनी पंजों में आ चुकी है और देश का शासक वर्ग कार्पोरेट के एजेंट की भूमिका में उतर आया है। जनता का पैसा कार्पोरेट के विकास में लगे और जनता को भान न हो, ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं।'[1] सरकार भारी संख्या में लाभजनक उपक्रमों को निजी हाथों में देने में अभूतपूर्व तत्परता दिखलाने के साथ-साथ बेख़ौफ़ होकर सुरक्षा तक से जुड़े उपक्रमों में 100 प्रतिशत एफडीआई लागू कर रही है।

हर साल दो करोड़ नौकरियां दिलाने का वादा कर सत्ता में आई सरकार ने केंद्र की भर्तियों में 89 प्रतिशत तक की कटौती कर दिया है। बीते मार्च में इसकी पुष्टि करते हुए सरकार की ओर से बताया गया था कि 2013 में 1,51,841 नौकरियां दी गयी थीं, जो 2014 में घटकर 1,26,261 रह गयीं और 2015 में केवल 15,877 लोगों की सीधी भर्ती की गई। सरकार बुलेट ट्रेन की नीव रख दी है किन्तु रेलवे में दो लाख खाली पड़े पद नहीं भर रही है। इस दौर में देश की शान समझी जाने वाली इंडियन एयर लाइन्स और रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में देने की तैयारी शुरू हो चुकी है और सरकारी अस्पतालों, बैंकों, स्कूलों, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की हालत सुनियोजित तरीके से पतली की जा रही है ताकि इन क्षेत्रों को निजी हाथों में देने की मांग खुद जनता ही उठाने लगे। इसके लिए सरकार समर्थक बुद्धिजीवी और मीडिया भी माहौल बनाने में जुट गयी है। 'अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक हैं नौकरियां हैं, लेकिन हम रोजगार के मौके कम होते देख रहे हैं। सेंटर

फॉर मॉनिटरिंग ऑफ़ इंडियन इकॉनमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2017 से अप्रैल 2017 के दौरान 15 लाख छीन गयीं। सालाना 2 करोड़ नौकरियों पैदा करने के अपने वादे को अनदेखा करते हुए प्रधानमंत्री ने नौकरियां मांगने की बजाय पैदा करने की नसीहत दे डाली है।'[2] कुल मिलाकर जिस आरक्षण के सहारे मूलनिवासी राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ रहे थे, उसे 24 जुलाई, 1991 को लागू नव उदारवादी अर्थिनीति के जरिये कागजों तक सिमटाने का जितना काम नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने दो दशकों में किया, उतना मोदी ने प्रायः तीन वर्षो में कर दिखाया है। ऐसी स्थिति में जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सामने रखकर राम मंदिर के जरिये संघ परिवार 2019 का आम चुनाव जीतने की परिकल्पना कर रहा है, तब मैं यह सवाल राष्ट्र की जरुरत : राम मंदिर या सामाजिक अन्यायमुक्त भारत लेकर पाठकों के बीच जाने का मन बनाये बिना न रह सका। बहरहाल आने वाले दिनों में मंदिर की आग देश को एक बार फिर बुरी तरह झुलसाने जा रही है, इस पर खुद हमारे विद्वान साक्षात्कारदाताओं तक को संदेह व्यक्त किया है। किन्तु देश मंदिर की आग में जलने जा रहा है, यह मानकर चलना ही राष्ट्र के लिए के श्रेयष्कर होगा, ऐसा मेरा मानना है।

खैर, यूपी में योगी की ताजपोशी के बाद मंदिर को लेकर भयावह भविष्य के संकेत एकाधिक बार मिले और ऐसा ही कुछ सन्देश इन पंक्तियों को लिखने के दौरान एक बार फिर मिल रहे हैं। आज 18 अक्तूबर, 2017 को मैं इस किताब की लेखकीय लिखने के लिए कलम उठाया हूँ। इसके लिए विगत तीन-चार दिनों से खुद को एकाग्र करने लगा था। तीन-चार दिनों के इस छोटे से अन्तराल में ऐसी कई बातें सुर्खियाँ बटोरी जिनसे लगा मंदिर को लेकर मेरी आशंका गलत नहीं है।

ताज पर विवाद

16 अक्तूबर के तमाम अखबार मुजफ्फरनगर और बिसाहड़ा के अख़लाक़ कांड से चर्चा में आये विधायक संगीत सोम ने एक जनसभा में ताजमहल पर विवादित टिपण्णी कर देश का माहौल उतप्त कर दिया। उन्होंने अपने संबोधन में मुग़ल शासकों बाबर, अकबर, और औरंगजेब को किताबों से हटाने का एलान करते हुए महाराणा प्रताप, एवं शिवाजी के ऐतिहासिक महत्त्व को नए सिरे से स्थापित करने की बात पुरअसर तरीके से कहा। एक ऐसे समय में जबकि पर्यटन की किताबों से ताजमहल हटाने से उपजे विवाद को थामने के लिए प्रदेश सरकार ने 370 करोड़ का टूरिज्म प्रोजेक्ट पेश किया, जिसमें 156 करोड़ रूपये ताजमहल पर खर्च होने की बात कही गयी है,'[3] माहौल गर्माने में चैम्पियन सोम ने उस सभा में ताज पर तंज कसते हुए कह दिया कि ताजमहल को किताबों से हटाने

के बाद तमाम लोगों को काफी दर्द हुआ है। उनके उस बयान के बाद तमाम चैनल उस पर बहस करवाने में मुस्तैद हो गए।

'नव्य अयोध्या'

इसी बीच 17 अक्तूबर के तमाम अख़बार संगीत सोम के ताज वाले बयान और 18 अक्तूबर को अयोध्या में आयोजित होने वाली ऐतिहासिक दीवाली से जुड़ी सूचनाओं से पटे दिखे। इनमें 'नव्य अयोध्या' से जुड़ी खबर काफी महत्वपूर्ण रही। इसके विषय में बताते हुए दैनिक जागरण ने लिखा है—'योगी सरकार अयोध्या को देश और दुनिया के पर्यटन के नक्शे पर पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में घोषित परियोजनाओं के अतिरिक्त अयोध्या में ही भगवान् श्रीराम को केंद्र बनाकर 'नव्य अयोध्या' बसाने की तैयारी है। 'नव्य अयोध्या' गोरखपुर और फैजाबाद को जोड़ने वाली पुरानी सड़क के बीच बसेगा। इसमें रामायण म्यूजियम, रामकथा संकुल और अत्याधुनिक बस अड्डा बनेगा। विमानन विभाग की रीजिनल कनेक्टिविटी योजना के तहत निकट भविष्य में अयोध्या को हवाई सेवा से भी जोड़ा जाएगा। रामायण म्यूजियम और रामकथा संकुल में जहां श्रद्धालु और पर्यटक लाईट एंड साउंड शो के जरिये पूरी रामायण को जीवंत रूप में देख सकेंगे। यहाँ से निकलने पर म्यूजिकल फाउन्टेन थीम पार्क से निकलती सुन्दरकाण्ड की सुरीली धुन का प्रस्तावित रिवर फ्रंट पर बैठकर आनंद ले सकेंगे। पर्यटकों की सुविधा के मद्देनजर एक हिस्सा हास्पिटलटी सेक्टर के लिए होगा।

गुप्तार घाट जहां श्रीराम ने जलसमाधि ली थी, उस ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा संस्थान खुलने को है है जहां राम और उनके जीवन से जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में सारा साहित्य और जानकारी उपलब्ध हो। प्रयास यह है कि पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले हिन्दू अगर भारत आते हैं तो वह एक बार अयोध्या आयें और रुके।'[4]

अयोध्या में ऐतिहासिक दीपोत्सव

18 अक्तूबर को होने वाले दीपोत्सव के विषय में अख़बार बता रहे थे कि चौदह वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम की वापसी की प्रसन्नता में अयोध्या का आनंद असीमित था। तब अयोध्यावासियों ने दीपावली मनाई और फिर यह प्रति वर्ष मनाई जाने लगी। यही दृश्य बुधवार फिर साकार होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया जायेगा। सोमवार को इसी की तैयारियों का रिहर्सल किया गया। रिहर्सल में ही भव्यता इतनी थी कि दर्शक अभिभूत हो उठे। दीपोत्सव का आरंभ बुधवार की सुबह प्रायः सात बजे

मध्य प्रदेश की विजावर रियासत की रानी की भक्ति के गवाह कंचन-मंदिर से 'हेरिटेज वाक' के साथ होगा। पर्यटनमंत्री डॉ. रीता बहुगुणा जोशी के साथ हेरिटेज ऑफ़ वाक में धर्म, संस्कृति, पर्यटन आदि क्षेत्रों से जुड़े दो सौ लोग शामिल होंगे। विरासत से सरोकार स्थापित करने का सन्देश देती हेरिटेज वाक दो किलोमीटर दूर भोलेबाबा के पौराणिक मंदिर नागेश्वरनाथ पहुंचकर समाप्त होगी।'[5] बहरहाल यह महज संयोग नहीं कि प्रधानमंत्री ने अयोध्या की ऐतिहासिक दिवाली के एक दिन पहले विरासत पर जोरदार सन्देश दे डाला।

उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित करते हुए दिल्ली से सन्देश दिया, 'कोई भी देश विकास की कितनी भी चेष्टा करे वो तबतक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक वो अपने इतिहास, अपनी विरासत पर गर्व करना नहीं जानता। अपनी विरासत को छोड़कर आगे बढ़ने वाले देशों की पहचान ख़त्म होनी तय है। ..आज मुझे गर्व है कि जो हमारी विरासत, जो श्रेष्ठ है, उसकी प्रतिष्ठा जन-जन के मन में स्थापित हो रही है।'[6] प्रधानमंत्री का यह सन्देश 18 अक्तूबर के तमाम अखबारों में छाया रहा। लेकिन प्रधानमंत्री के बयान के समान ही 18 अक्तूबर के तमाम अख़बारों में यह खबर छपी थी, 'राम के लिए सजी अयोध्या, रामनगरी में जीवंत होगा त्रेता युग जैसा राज्याभिषेक; उम्मीदों के पुष्पक विमान से आयेंगे 'भगवान राम' मुख्यमंत्री योगी करेंगे अगवानी; दीपावली से एक दिन पहले सरयू में आसमान के तारों की तरह जगमगायेंगे 1.71 लाख दीप; कल्याण सिंह के शासन काल में 1991 के बाद पहली बार अयोध्या में भगवान राम को केंद्र में रखकर कोई हलचल है।'[7] और 18 अक्तूबर की शाम को जब मैं टीवी के सामने बैठा तो पाया कि गत तीन-चार दिनों से अख़बारों में जो छप रहा था, वही टीवी पर रूपांतरित हो रहा है। फर्क एक ही रहा जहां पहले 1.71 लाख दीप जलने वाले थे वहां 1.87 लाख जले और शानदार तरीके से गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड में दर्ज हुआ। टीवी पर दीपोत्सव के भव्य दृश्यों के साथ-साथ राम मंदिर निर्माण से जुड़े तरह-तरह के सन्देश दिख रहे थे। अयोध्या में योगी के दीये से 2019 में जीतेंगे मोदी; राम मंदिर के लिए मोदी के दूत बने योगी; अयोध्या सज गयी, राम मंदिर भी बनेगा-सुब्रह्मनियम स्वामी; राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा-विनय कटियार; नए सिरे से राम मंदिर में जान फूंकने की कोशिश; तिरपाल में रामलला का आखिरी साल; पहली बार सारे संत एक साथ मंच पर; मंदिर बनेगा और योगी के राज में बनेगा; इसी दिसंबर में राम मंदिर बनने की सूचना मिल जाएगी..आदि-आदि।

बहरहाल 16 को सोम का 'ताज' और 17 अक्तूबर को मोदी के' विरासत' सम्बन्धी बयान कहीं न कहीं 18 अक्तूबर को अयोध्या में आयोजित इतिहास के सबसे बड़े दीपोत्सव के लिए माहौल बनाने के उद्देश्य से ही जारी किये गए थे, ऐसा राजनीतिशास्त्र के प्राइमरी स्तर तक के विद्यार्थी भी उपलब्धि किये होंगे। और

दीपोत्सव के लिए माहौल बनाने का मतलब राम मंदिर के लिए माहौल बनाना है। ऐसे में अयोध्या दीपोत्सव के बाद अब रत्ती भर भी संदेह नहीं रहना चाहिए कि आने वाले दिनों में संघ परिवार 2019 का चुनाव जीतने के योगी के नेतृत्व देश राम मंदिर का बवंडर खड़ा करने जा रहा है.

भाजपा को शिकस्त देना पहले से कठिन!

बहरहाल, 2019 में भाजपा को सत्ता में आने से रोकना बहुत ही जरुरी है। कारण, अगर भाजपा फिर सत्ता में आ जाती है तो बहुजनों के बचे-खुचे शक्ति के स्रोत भी पूरी तरह बंद कर देगी। खैर! भाजपा को रोकने के लिए बहुजन बुद्धिजीवियों की तरफ से महागठबंधन बनाने तथा बिहार विधानसभा चुनाव-2015 की भांति भविष्य के चुनावी मुद्दे को सामाजिक न्याय पर केन्द्रित करने का सुझाव आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा को शिकस्त देने के लिए बिहार मॉडल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज के दौर को भयावह बनाने वाली भाजपा को 2019 में रोकने लिए विपक्ष महागठबंधन के निर्माण के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की भांति सामाजिक न्याय का मुद्दा स्थिर करता है तो भी गत दो-तीन माह में जो हालात बनें हैं, उसमें भाजपा को शिकस्त देना पहले के मुकाबले एकाधिक कारणों से बहुत कठिन हो गया है।

नीतीश की पलटी

भाजपा को रोकने लिए लालू-नीतीश गठबंधन वाले जिस मॉडल की सामाजिक न्यायवादी मिसाल देते थे, जुलाई के शेष में नीतीश कुमार के भाजपा से हाथ मिला लेने के बाद उसके परखचे उड़ गए। उनकी राजनीतिक-वैचारिक पलटी की कीमत बिहार को ही नहीं, पूरे देश को चुकानी पड़ेगी, ऐसा अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। ऐसे लोगों के अनुसार उनकी चाल ने बिहार में महागठबंधन को ही ध्वस्त नहीं किया, जिसने आम चुनाव में जबरदस्त कामयाबी के बाद, खुद को अजेय मान रहे मोदी के विजय रथ को रोका था बल्कि इसने ज्यादा से ज्यादा सांप्रदायिक, तानाशाहीपूर्ण तथा कार्पोरेटपरस्त दिखाई दे रहे मोदी राज के खिलाफ एक वास्तविक विकल्प की कल्पनाओं पर भी भारी आघात किया है।[8] महागठबंधन की संभावना पर नीतीश ने जैसा प्रबल आघात किया है, उसके बाद से महागठबंधन की बात पर काफी हद तक विराम सा लग गया है। बहरहाल नीतीश की पलटी के बावजूद 2019 में भाजपा के सत्ता से आउट होने की सम्भावना काफी हद तक बनी रहती यदि बहुजन नेतृत्व मृतप्राय नहीं हुआ होता।

मृतप्राय बहुजन नेतृत्व

इस पुस्तक के अध्याय-1 में जो मेरे लेख छपे हैं, उनमें मैने भाजपा को रोकने लिए बहुजन नेताओं के समक्ष चुनावी मुद्दे को सामाजिक न्याय पर केन्द्रित करने का बार-बार मैंने आह्वान किया था। प्रायः ऐसा ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर सक्रिय असंख्य बहुजन बुद्धिजीवियों ने किया। चुनाव को सामाजिक न्याय पर केन्द्रित करके ही भाजपा को मात दिया जा सकता है, यह जानते हुए भी बहुजन नेतृत्व ने उसकी बुरी तरह अनदेखी कर दिया। चुनाव अगर सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ा जाता, कम से कम यूपी में तो भाजपा नहीं ही जीतती, यह बिहार विधानसभा चुनाव- 2015 के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह मोहन भागवत ने आरक्षण पर बयान देकर चुनाव को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर केन्द्रित करने का अवसर दे दिया था, कुछ वैसा ही अवसर यूपी में भी मिला था पर, यूपी का बहुजन नेतृत्व उसका सद्व्यवहार करने में कोई रूचि नहीं लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2009 से अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर बहुजन नेतृत्व ने सवर्णपरस्ती का जो दामन थामा'[9], उसके बाद वह मृतप्राय हो गया : सामाजिक न्याय की उग्र हिमायत से दूर होते गया। लेकिन 11 मार्च, 2017 के बाद उम्मीद बंधी थी कि वह अपनी वजूद रक्षा के लिए एक बार फिर सामाजिक न्याय के पक्ष में अलख जगाने के लिए खुलकर सामने आएगा। विगत छः माह में ऐसे कई अवसर आये भी पर, वह पूर्व की भांति सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाने से बचता रहा। ऐसे में उसके ठंडापन को देखते हुए दावे के साथ कहा जा सकता है कि देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले यूपी का बहुजन नेतृत्व मृतप्राय हो चुका है और 2019 में शायद वह भाजपा को योग्य चुनौती देने की स्थिति में नहीं रह पायेगा।

योग्य नेतृत्व का अभाव

निराशा के इस दौर में लालू प्रसाद यादव का तेवर बहुजनों में उम्मीद का संचार जरुर करता है। लेकिन जिस तरह से वह भ्रष्टाचार के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं, 2019 के प्रति उनसे भी कोई विशेष उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ऐसे में ले देकर एक मात्र **शरद यादव** के प्रति ही कुछ आशावादी हुआ जा सकता है। बेदाग़ शरद यादव बौद्धिक रूप से बहुजनों के सबसे सक्षम नेता हैं। उनसे बहुजन समाज 1974 वाले जेपी की भूमिका अख्तियार करने के आश लगाये हुए है। किन्तु जिस हथियार से भाजपा को शेष किया जा सकता है, सामाजिक न्याय के उस अमोघ हथियार के प्रति वह खुलकर अपना रुख नहीं जाहिर कर

रहे है। ऐसे में बहुजनवादी दलों में योग्य नेतृत्व का अभाव भी भाजपा के पक्ष में जाता दिख रहा है।

सावधान! मोदी को सामाजिक न्याय का नया मसीहा बनाने कि तैयारी चल रही है

मार्च में पांच राज्यों का चुनाव परिणाम आने के बाद से भाजपा सदियों से शक्ति के स्रोतों पर 80-85 प्रतिशत कब्ज़ा जमाये विशेषाधिकारयुक्त व सुविधासंपन्न वर्ग को और संपन्न तथा मूलनिवासियों को पूरी तरह शक्तिहीन करने की सुपरिकल्पित योजना के तहत जहां एक ओर आरक्षण के खात्मे की कार्ययोजना पर और मुस्तैद हुई, वहीं दूसरी ओर वह 23 अगस्त, 2017 से आरक्षित वर्गों की एकता को पूरी तरह ध्वस्त करने के कुत्सित इरादे से आरक्षण के वर्गीकरण अर्थात बंदरबांट के मोर्चे पर पूरी तरह मुस्तैद हो गयी है। फिलहाल तो यह प्रयोग ओबीसी पर होने जा रहा है पर, बाद में इसके दायरे में एससी/एसटी का आरक्षण भी आना तय है। बहरहाल 'मोदी सरकार का यह निर्णय जाति की राजनीति का एक नया दौर शुरू कर देगा। ओबीसी जातियों में यह विभाजन तो पहले से ही है, लेकिन इसके कारण वह विभाजन औपचारिक रूप प्राप्त कर लेगा।'[10]

आरक्षण का वर्गीकरण करने के फलस्वरूप चिरकाल से अभावों में रहे आरक्षित वर्ग के लोग, अपने नाममात्र के फायदे को देखते हुए मोदी को सामाजिक न्याय का नया मसीहा मानने लग सकते हैं, जो कि भाजपा की योजना है। और जिस तरह देश की प्रायः सम्पूर्ण मीडिया, साधु-संत और सवर्ण लेखक-विद्वान भाजपा के साथ हो लिए हैं, उससे मुमकिन है कि बहुजन समाज की आरक्षण से कम लाभान्वित जातियां, मोदी को मसीहा मानने भी लगें। अगर ऐसा होता है तब तो सामाजिक न्याय का बिहार जैसा मुद्दा बेअसर हो जायेगा। ऐसे में आज सबसे बड़ी जरुरत आरक्षित वर्गों की टूटी-फूटी एकता को बचाए रखना है, जो आसान नहीं है। इस खतरे ने भी 2019 में बहुजनवादी दलों की सम्भावना को कमतर कर दिया है।

बहरहाल पांच राज्यों के चुनाव के बाद भाजपा जहां एक ओर आरक्षण के वर्गीकरण के जरिये पहले से कमजोर बहुजन एकता को भविष्य में खंड-खंड कर खुद की स्थिति और सुरक्षित करने जा रही है, वहीं अपनी शक्ति में इतना विस्तार कर ली है, जिसकी कल्पना कर विपक्ष के पसीने छूट जाएँ। इसका खुलासा मैंने 'भाजपा की शक्ति के स्रोत' नामक अपने लेख में किया है।

भाजपा की शक्ति के स्रोत

मैंने भाजपा के शक्ति के स्रोतों को चिन्हित करते हुए लिखा है, 'यह तय

सा दिख रहा है कि भाजपा को रोकने के लिए भविष्य में न सिर्फ राजनीतिक दलों, बल्कि बुद्धिजीवियों का भी मोर्चा वजूद में आयेगा। ऐसे में जिस भाजपा के पास विश्व में सर्वाधिक, 10 करोड़ से ज्यादे सदस्य हैं ;13 राज्यों में खुद की एवं 4 राज्यों में गठबंधन की सरकार चला रही जो भाजपा 1489 विधायकों तथा 283 सांसदों की संखाबल से समृद्ध है, उसके शक्ति के स्रोतों की सटीक जानकारी विपक्ष के लिए बहुत जरुरी है। अब जहाँ तक भाजपा की शक्ति के स्रोतों का प्रश्न है, हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह इसकी शक्ति के स्रोतों का भी अंत पाना आसान नहीं है। फिर भी इसके दस ऐसे प्रमुख स्रोतों को चिन्हित किया जा सकता है, जिसके बूते वह आज की तारीख में भारत के चप्पे-चप्पे पर कब्ज़ा ज़माने की संभावना उजागर कर दी है। बहरहाल 1925 की विजयादशमी को आधुनिक भारत के सर्वाधिक दूरदर्शी ब्राह्मण नेता डॉ.केशवराव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही भाजपा की शक्ति का प्रमुख स्रोत है, इस बात से शायद ही किसी की असहमति हो। अपने किस्म के विश्व के इकलौते संगठन आरएसएस के भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, राष्ट्रीय सेविका समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिन्दू परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बजरंग दल, अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ परिषद, लघु उद्योग भारती, भारतीय विचार केंद्र, विश्व संवाद केंद्र, राष्ट्रीय सिख संगठन, विवेकानंद केंद्र और खुद भारतीय जनता पार्टी सहित दो दर्जन से अधिक आनुषांगिक संगठन हैं, जिनके साथ 28 हजार, 500 विद्यामंदिर, 2 लाख, 80 हजार आचार्य, 48 लाख, 59 हजारछात्र, 83 लाख, 18 हजार, 348 मजदूर, 595 प्रकाशन समूह, 1 लाख पूर्व सैनिक, 6 लाख, 85 हजार वीएचपी-बजरंग दल के सदस्य जुड़े हुए है। यही नहीं इसके साथ बेहद समर्पित व इमानदार 4 हजार पूर्णकालिक कार्यकर्त्ता हैं, जो देश भर में फैले 56 हजार, 859 शाखाओं में कार्यरत 55 लाख, 20 हजार स्वयंसेवकों के साथ मिलकर इसके राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी को बल प्रदान करते हैं।'[11] इसके अतिरिक्त देश भर के हिन्दू लेखकों, मीडिया (प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक), साधु-संत, धन्नासेठों और सवर्ण मतदाताओं का प्रायः 90 प्रतिशत हिस्सा भाजपा के ही साथ है।'[12] लेकिन अपराजेय दिख रही महाशक्तिशाली भाजपा को 2019 में आसानी से शिकस्त दिया जा सकता है, यदि बहुजनवादी अपने शक्ति के स्रोत का सम्यक करें तो।

बहुजनवादी दलों की शक्ति का स्रोत : सामाजिक अन्याय का शिकार विशालतम आबादी

पिछले दिनों मैंने एक खास लेख लिखा था, जो इस पुस्तक के पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। उसमें लिखा था, 'गत दिनों इसी अखबार में भाजपा की शक्ति

के स्रोतों पर आलोकपात करते हुए मैंने बताया था कि दुनिया के विरल व विराट संगठन, आरएसएस के अतिरिक्त देश भर के लेखकों, मीडिया (प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक), साधु-संतों, सवर्ण मतदाताओं का 90 प्रतिशत हिस्सा भी उसे शक्ति प्रदान करता है। शक्ति के इन स्रोतों को सौ के बराबर अकेला करिश्माई नरेंद्र मोदी सैलाब में परिणत कर भाजपा को अप्रतिरोध्य बना दिए हैं। भाजपा के शक्ति के स्रोतों का अपार भंडार देखकर ऐसा लग सकता है कि बहुजनवादी दल अप्रिरोध्य भाजपा के समक्ष बिलकुल असहाय हैं। न तो इनके पास संघ के मुकाबले दस प्रतिशत की भी हैसियत रखने वाला कोई सामाजिक संगठन है, और न ही धनपतियों, मीडिया, लेखकों का न्यूनतम समर्थन ही प्राप्त है। मोदी जैसे करिश्माई नेता की बहुजनवादी दलों तो क्या, दूसरे सवर्णवादी गैर-भाजपाई दलों तक में भी कल्पना करना दुष्कर है। पर, यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सत्ता हासिल करने में संख्याबल सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण फैक्टर का काम करता और इसी संख्या-बल को ही अपने अनुकूल करने के लिए पार्टियों को धन-बल, मीडिया-बल, प्रवक्ताओं-कार्यकर्ताओं की भीड़ और कुशल नेतृत्व की जरुरत पड़ती है तो पता चलेगा भारत के बहुजनवादी दलों जैसी अनुकूल स्थिति पूरी दुनिया में अन्यत्र दुर्लभ है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में सदियों से सामाजिक अन्याय का शिकार बनाई गयी भारत के बहुजन समाज जैसी विपुल आबादी दुनिया में कहीं है ही नहीं।'[13]

'वैसे तो सामाजिक अन्याय की कोई निर्दिष्ट परिभाषा नहीं है किन्तु, विभिन्न समाज विज्ञानियों के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि नस्ल, जाति, लिंग, धर्म, भाषा, क्षेत्रादि के आधार पर विभाजित समाज के विभिन्न सामाजिक समूहों में से कुछेक का शासकों द्वारा शक्ति के स्रोतों से जबरन बहिष्कार ही सामाजिक अन्याय का कहलाता है। इस लिहाज से दुनिया में स्त्री के रूप में विद्यमान आधी आबादी सर्वत्र ही सामाजिक अन्याय का शिकार रही। सर्वाधिक अन्याय के शिकार समुदायों में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत तथा भारत के बहुजन रहे हैं। इनमें भारत के बहुजनों को ही शीर्ष पर रखा जा सकता है।'[14]

बहुजनों की सापेक्षिक वंचना : भाजपा के खिलाफ साबित हो सकती है बारूद का ढेर!

सदियों पूर्व सामाजिक अन्याय का शिकार बनायीं गयी तमाम कौमें, इससे निजात पा चुकी हैं, अपवाद हैं तो भारत की मूलनिवासी जातियां। कुल मिलाकर उपरोक्त तथ्य यह गवाही देते हैं कि आधुनिक विश्व में भी सर्वाधिक अन्याय की शिकार विशालतम आबादी की उपस्थिति भारत में ही है। यह आबादी इस अन्याय की गुफा से निकलने के लिए बुरी तरह छटपटा रही है। भारत में सामाजिक अन्याय

की शिकार विश्व की विशालतम आबादी को जिस तरह विषमता का शिकार होकर जीना पड़ रहा है, उससे भारत में विशिष्ट क्रन्तिकारी आन्दोलन पनपने की 'निश्चित दशाएं' साफ़ दृष्टिगोचर होने लगीं हैं। समाज विज्ञानियों के मुताबिक़ क्रांतिकारी आन्दोलन मुख्यतः असंतोष, अन्याय, उत्पादन के साधनों का असमान बंटवारा तथा उच्च व निम्न वर्ग के मध्य व्याप्त खाई के फलस्वरूप होता है। सरल शब्दों में ऐसे आन्दोलन आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी की कोख से जन्म लेते हैं और तमाम अध्ययन साबित करते हैं कि भारत जैसी भीषण गैर-बराबरी पूरे विश्व में कहीं है ही नहीं।

इस क्रान्तिकारी आन्दोलन में बहुजनों में पनपता 'सापेक्षिक वंचना' का भाव आग में घी का काम करता है, जो वर्तमान भारत में दिख रहा है। क्रांति का अध्ययन करने वाले तमाम समाज विज्ञानियों के मुताबिक़ जब समाज में सापेक्षिक वंचना का भाव पनपने लगता है, तब आन्दोलन की चिंगारी फूट पड़ती है। समाज विज्ञानियों के मुताबिक़, 'दूसरे लोगों और समूहों के संदर्भ में जब कोई समूह या व्यक्ति किसी वस्तु से वंचित हो जाता है तो वह सापेक्षिक वंचना है। दूसरे शब्दों में जब दूसरे वंचित नहीं हैं, तब हम क्यों रहें!' जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हजारों साल के विशेषाधिकारयुक्त व सुविधासंपन्न सवर्णों के शक्ति के तमाम स्रोतों पर ही 80-90 प्रतिशत कब्जे ने बहुजनों में सापेक्षिक वंचना के अहसास को प्रायः तुंग पर पहुंचा दिया है। और इतिहास गवाह है जब बहुसंख्य लोगों में यह भाव पनप जाता है, क्रांतिकारी आन्दोलन भड़कने में देर नहीं लगती। सापेक्षिक वंचना का भाव क्रान्तिकारी आन्दोलन की एक और शर्त पूरी करता दिख रहा है और वह है 'हम-भावना' का तीव्र विकास। कॉमन वंचना ने बहुजनों को शक्तिसंपन्न वर्गों के विरुद्ध 'हम-भावना' से लैस करना शुरू कर दिया है। इस भयावह विषमता का सदव्यवहार कर बहुजन साहित्यकार विशिष्ट आन्दोलन लायक हालात बनाने में जुट गए हैं।

एक ही कमी : योग्य बहुजन नेतृत्व!

बहरहाल आज भारत में विशिष्ट क्रांतिकारी आन्दोलन के उभार की प्रायः सारी स्थितियां और परिस्थितियां तैयार हैं। लेकिन ऐसे आंदोलनों के लिए जरुरत होती है एक योग्य नेतृत्व की, जो आन्दोलन के लिए पूंजीभूत हुई आदर्श स्थितियों का सदव्यवहार कर सके, जिससे कि सम्पदा-संसाधनों और अवसरों के न्यायोचित बंटवारे का मार्ग प्रशस्त हो। बहुजनों का दुर्भाग्य है कि अवसरों के सदव्यवहार लायक इस समय कोई उपयुक्त नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व की इन्हीं कमियों का लाभ उठाकर भाजपा ने बैलेट बॉक्स के जरिये एक प्रतिक्रान्ति कर दी है। लेकिन बहुजन नेतृत्व यदि खुद को इन अनुकूल स्थितयों के सदव्यवहार के लिए तैयार कर ले, जो खूब असंभव भी नहीं है, तो बैलेट बॉक्स के जरिये भारत में क्रांति बहुत आसानी

से घटित हो सकती है अर्थात भाजपा बहुजनवादी दलों के समक्ष पराजित हो सकती है।'[15]

सापेक्षिक वंचना के सद्व्यवहार के लिए : डाइवर्सिटी

इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह ' प्राचीन विशेषाधिकारयुक्त तबके का सदियों से ही शक्ति के स्रोतों पर प्रायः सम्पूर्ण एकाधिकार रहा और आज भी उनका उद्योग-व्यापार, शासन-प्रशासन, शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्रोतों पर 80-85 प्रतिशत कब्ज़ा है तथा जो 15-20 प्रतिशत अवसर वंचितों को सुलभ हैं, उन्हें भी जिस तरह मोदी सरकार अपनी आर्थिक नीतियों के जरिये शक्तिशाली तबकों के हिस्से में डालने में सर्वशक्ति लगा रही है,'[16] उसका हवाला देकर सापेक्षिक वंचना (Relative deprivation) के अहसास को तुंग पर पहुँचाया जा सकता है। लेकिन इस वंचना का सदव्यवहार तभी हो सकता है जब विपक्ष विशाल वंचित आबादी के समक्ष वैसी कर्मसूची रखे, जिससे उन्हें लगे कि इसके जरिये वे भी परम्परागत व विशेषाधिकारयुक्त तबकों की भांति शक्ति के समस्त स्रोतों को भोग करने की स्थिति में आ सकते हैं। और इसमें कोई दो मत नहीं कि ऐसी कर्मसूची सिर्फ और सिर्फ बहुजन लेखकों द्वारा स्थापित 'बहुजन डाइवर्सिटी मिशन' के डाइवर्सिटी एजेंडे में ही है। इसके तरफ से निम्न क्षेत्रों में सामाजिक और लैंगिक विविधता का प्रतिबिम्बन कराने अर्थात विविधतामय भारत के चार सामाजिक समूहों-सवर्ण, ओबीसी, एससी/एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यकों- के स्त्री-पुरुषों की संख्यानुपात में अवसरों के बंटवारे की दस सूत्रीय कर्मसूची स्थिर की गईं हैं।

1-सेना व न्यायालयों सहित सरकारी और निजीक्षेत्र की सभी स्तर की, सभी प्रकार की नौकरियों व धार्मिक प्रतिष्ठानों अर्थात पौरोहित्य; 2-सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा दी जानेवाली सभी वस्तुओं की डीलरशिप; 3-सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा की जानेवाली सभी वस्तुओं की खरीदारी; 4-सड़क-भवन निर्माण इत्यादि के ठेकों, पार्किंग, परिवहन; 5-सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा चलाये जानेवाले छोटे-बड़े स्कूलों, विश्वविद्यालयों, तकनीकि-व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के संचालन, प्रवेश व अध्यापन; 6-सरकारी और विदेश की संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) को दी जानेवाली धनराशि; 8-प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं फिल्म-टीवी के सभी प्रभागों; 9-रेल-राष्ट्रीय मार्गों की खाली पड़ी भूमि सहित तमाम सरकारी और मठों की खाली पड़ी जमीन व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए अस्पृश्य-आदिवासियों में वितरित हो एवं 10-ग्राम-पंचायत, शहरी निकाय, संसद-विधासभा की सीटों;राज्य एवं केन्द्र की कैबिनेट;विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालयों;विधान परिषद-राज्यसभा;राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के कार्यालयों इत्यादि...[17]

सामाजिक अन्यायमुक्त भारत निर्माण बने चुनावी मुद्दा

जैसा कि पिछली पंक्तियों में कहा गया है कि समाज के विभिन्न सामाजिक समूहों में से कुछेक का शासकों द्वारा शक्ति के स्रोतों से जबरन बहिष्कार ही सामाजिक अन्याय का कहलाता है। अगर शक्ति के स्रोतों से बहिष्कार ही सामाजिक अन्याय का सबब है तो अवश्य ही उपरोक्त क्षेत्रों में वंचित सामाजिक समूहों को वाजिब हिस्सेदारी सुलभ कराकर सामाजिक अन्यायमुक्त भारत का निर्माण कराया जा सकता है। और इसमें सर्वाधिक कारगर हो सकता है बीडीएम का दस सूत्रीय एजेंडा। क्योंकि डाइवर्सिटी के उपरोक्त एजेंडे के दायरे में शक्ति के समस्त स्रोत (आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, धार्मिक सांस्कृतिक इत्यादि) आ जाते हैं, जिनसे सदियों से दूर धकेलकर ही बहुजनों को अन्याय का शिकार गया। इसीलिए मैंने साक्षात्कार की प्रश्नावली संख्या 9 में कहा है-'जब भी चुनाव में सामाजिक न्याय के मुद्दे को हवा दी जाती है, भाजपा उद्भ्रांत हो जाती है और हार वरण करने के सिवाय उसके सामने कोई चारा नहीं रहता। ऐसे में विपक्ष यदि मिलिट्री-पुलिस, न्यायपालिका सहित सरकारी और निजी क्षेत्र की परमानेंट, संविदा तथा आउट सोर्सिंग वाली नौकरियों के साथ सभी प्रकार के ठेकों, सप्लाई-डीलरशिप, पार्किंग-परिवहन, फिल्म-मीडिया इत्यादि तमाम क्षेत्रों एससी/एसटी, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के संख्यानुपात में भागीदारी दिलाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ें, अप्रतिरोध्य भाजपा की लोकसभा चुनाव-2019 में ही बिहार विधानसभा चुनाव -2015 जैसी स्थिति हो जाएगी, इसकी निर्भूल घोषणा राजनीति शास्त्र का एक अदना सा विद्यार्थी भी कर सकता है। ऐसे में मेरा मानना है कि विपक्ष सामाजिक अन्याय-मुक्त भारत निर्माण के मुद्दे पर चुनाव लड़कर भाजपा को हमेशा के लिए लुंज-पुंज कर सकता है। कुछ ऐसा ही सवाल मैंने प्रश्न सख्या 10 में भी किया है। इन प्रश्नों पर विद्वानों की राय बहुत ही उत्साहवर्द्धक रही है। सभी ने ही प्रायः यह कहकर डाइवर्सिटी और सामाजिक अन्यायमुक्त भारत निर्माण का समर्थन किया है कि इससे राम मंदिर का मुद्दा हाशिये पर चला जायेगा और भाजपा लुंज-पुंज हो जाएगी

मोदी को सामाजिक न्याय का मसीहा बनाने के मंसूबों पर : डाइवर्सिटी फेर सकती है पानी

भाजपा द्वारा ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण के जरिये मोदी को सामाजिक न्याय का नया मसीहा और बहुजन एकता को आघात पहुँचाने का जो उपक्रम शुरू होने जा रहा है, उससे बहुजन बुद्धिजीवी बहुत चिंतित हैं, किन्तु डाइवर्सिटी इससे मुक्त कर सकती है। वह इसलिए कि कलहरत असंख्य जातियों में बंटे बहुजनों को अगर कोई चीज जोड़ती व निकट लाती है तो वह आरक्षण ही है। इसीलिए

Continue Your Reading Journey

This preview has ended. Access the complete library and support our mission.

Join Our Inclusive Reading Community

✓ We champion diverse voices and perspectives
✓ Your support helps amplify underrepresented authors
✓ We provide free access to educational institutions
✓ Building bridges through shared stories
✓ Creating space for all narratives to be heard

Support Our Mission

Your donation enables us to:
• Curate diverse book collections
• Support authors from marginalized communities
• Provide free resources to educators
• Maintain our accessible digital library

Visit: www.diversitymission.in

Sign the diversity pledge • Make a donation • Download full library